सभी पंचायतों में पैक्स समितियां बनें : शाह

भाषा
नई दिल्ली, 12 अगस्त

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी समितियों के जरिये 10 लाख करोड़ रुपये का कृषि-ऋण मुहैया कराने के लिए देश भर में दो लाख से अधिक नई प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के गठन की जरूरत है। शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि देश में फिलहाल 95,000 से अधिक पैक्स समितियां मौजूद हैं लेकिन उनमें से करीब 63,000 समितियां ही हैं। पैक्स समितियां कृषि क्षेत्र की कर्ज प्रणाली की आत्मा हैं लिहाजा उनका सशक्तीकरण और विस्तार जरूरी है। देश में तीन लाख पंचायतें हैं लेकिन पैक्स समितियां सिर्फ 95,000 ही है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में दो लाख से अधिक नई पैक्स समितियों के गठन की जरूरत है। शाह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से एक पंचवर्षीय योजना बनाने को कहा।

यूको बैंक UCO BANK
सम्मान आपके विश्वास का
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय – II,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3 और 4, डीडी ब्लॉक, सेक्टर-1,
साल्ट लेक, कोलकाता – 700064

निविदा की सूचना

यूको बैंक निम्नलिखित मदों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.) आमंत्रित करता है:-

1. ओपेक्स मॉडल पर शाखाओं और एटीएम के लिए समर्पित VSAT की आपूर्ति कमीशनिंग रखरखाव और प्रबंधन।
2. FEBA में यूजर इंटरफ़ेस और कस्टमाइजेशन में सुधार के लिए वेंडर का चयन।
3. बायोमेट्रिक उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (दर-अनुबंध)।
4. यूपीएस सिस्टम्स की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (दर-अनुबंध) (पुनः निविदा)।

किसी भी विवरण के लिए कृपया **https://www.ucobank.com** वेबसाइट पर देखें।

उप-महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

दिनांक : 13.08.2022

PUNJ LLOYD LIMITED (In Liquidation)
FOR SALE OF THE COMPANY AS A GOING CONCERN
under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Announcing the sale of "Punj Lloyd Limited (**"Company"** or **"Corporate Debtor"**)- In Liquidation" as a going concern pursuant to the Order of Hon'ble NCLT (New Delhi, Principal Bench) dated 27 May 2022 (**"Order"**). Pursuant to the aforementioned order, Mr. Ashwini Mehra has been appointed as the Liquidator of the Company.

The Liquidator, in furtherance of the Order and Invitation for Expression of Interest dated 28 June 2022 ("EOI"), is now issuing an invitation for submission of binding bid from Prospective Bidders for participation in the process for sale of the Company as a whole, on a going concern basis which shall be on an 'as is where is', 'as is what is', 'as is how is' and 'without any recourse' basis without any representation, warranty or indemnity by the Company, the Liquidator or any other person.

The Company incorporated in 1988, is a well-diversified business conglomerate, engaged in the business of Engineering, Procurement and Construction (**"EPC"**), with geographic presence across India and Middle East Countries offering services in Energy and Infrastructure along with manufacturing capabilities in the defence sector.

Interested Bidders can procure more details about the sale process by submitting their Expression of Interest pursuant to the Invitation dated 28 June 2022 to **LQ.Punj@in.gt.com** with copy to **mehra.ashwini@gmail.com**, **surendra.raj@in.gt.com** and **gauav.khera@in.gt.com.**

The timelines for sale process of the Corporate Debtor on a going concern basis and other details are as follows:

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the Corporate Debtor	**Punj Lloyd Limited**
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	26 September 1988
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	MCA, RoC-Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of Corporate Debtor	L74899DL1988PLC033314
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Punj Lloyd House17-18, Nehru Place New Delhi 110019
6.	Liquidation Commencement Date of the Corporate Debtor	Date of Order 27 May 2022, delivered on 31 May 2022
7.	Date of invitation for the submission of binding bids for acquisition of the Corporate Debtor as a going concern	13 August 2022
8.	Asset Sale Process Memorandum for submission of Binding bids	The Interested Bidder, who have not submitted EOI, can submit it along with other required documents to the Liquidator on the email id **LQ.Punj@in.gt.com**. Copy of EOI is published on website of the Company (Refer - **http://punjlloydgroup.com/liquidation-documents**) Upon satisfaction of the eligibility criteria by the Liquidator, the detailed Asset Sale Process Memorandum shall be shared with the interested bidders. The Interested Bidders who have already submitted the EOI and meet the eligibility criteria will be shared Asset Sale Process Memorandum on their official emails.
9.	Last date for the submission of binding bids	26 August, 2022
10.	Name and registration number of the Liquidator	Mr. Ashwini Mehra Regn. No. - IBBI/IPA-001/IP-P00388/2017-18/10706
11.	Address and email to be used for correspondence with the Liquidator	Mr. Ashwini Mehra, Liquidator Punj Lloyd Limited, C/O Mr. Surendra Raj Gang GT Restructuring Services LLP, L-41, Connaught Circus, New Delhi - 110001, E: **LQ.Punj@in.gt.com**
12.	Earnest Money Deposit to be submitted along with the Binding Bids	INR 10 Crore
13.	Communication of Reserve Price to Qualified Bidders	5 September 2022
14.	Tentative date of e-auction	6 September 2022
15.	E-auction portal	The Auction Sale will be done through the E-Auction platform: **https://ncltauction.auctiontiger.net**.

The Liquidator reserves the right to amend the key terms of the sale process including timelines for the Going Concern Sale Process to the extent permissible under the applicable laws and regulations. Any information about amendments /extension of any of the timelines will be available on the Corporate Debtor's website and communicated to the Qualified/ Successful Bidder.

Nothing contained herein shall constitute a binding offer or a commitment for sale of the Company as a whole, on a going concern basis.

Ashwini Mehra
(Reg No. IBBI/IPA-001/IP-P00388/2017-18/10706)
(Liquidator)
Punj Lloyd Limited - In Liquidation
Correspondence Address:
Mr. Ashwini Mehra, Liquidator
Punj Lloyd Limited
C/O Mr. Surendra Raj Gang
GT Restructuring Services LLP
L-41, Connaught Circus, New Delhi - 110001, E: **LQ.Punj@in.gt.com**
Registered address of Insolvency Professional with IBBI:
C 1201, Salarpuria Magnificia, Old Madras Rd. Bangalore-560016, E: **Mehra.Ashwini@gmail.com**

Date : 13 August, 2022
Place: New Delhi

स्वतंत्रता दिवस पर शानदार बिक्री की आस

शार्लीन डिसूजा
मुंबई, 12 अगस्त

देश को आजादी मिले 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और खुदरा कारोबारी इस थीम को भुनाने की कवायद में जुट गए हैं। खुदरा विक्रेता या तो सीजन की अपनी बिक्री के अंतिम चरण में हैं या अगले 3 दिन तक भारी छूट की पेशकश कर रहे हैं। कुछ रिटेलरों ने सीधे 50 प्रतिशत छूट की पेशकश की है। वहीं कुछ अन्य अपने थीम के साथ हैं और 75 प्रतिशत तक छूट की पेशकश कर रहे हैं।

पेपे जींस इंडिया के सीईओ मनीष कपूर ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'अब हम इस सीजन की बिक्री के अंतिम दौर में हैं, ऐसे में हमने अपनी इन्वेंट्री के 35-40 प्रतिशत पर बिक्री के आखिरी 3 दिन में सपाट 50 प्रतिशत छूट की पेशकश की है।'

अन्य कई प्रमुख ब्रांडों ने भी अपने कुछ ब्रांड पर अगले 3 दिन के लिए छूट की पेशकश की है। कंपनियों ने अपने सीजन की अंतिम बिक्री पिछले महीने पूरी की है और अब इस सप्ताहांत के लिए पेशकश कर रही हैं। एल्डो एक उत्पाद खरीदने पर दूसरे पर 75 प्रतिशत छूट (चुनिंदा उत्पादों पर) देने की पेशकश कर रही है। वहीं बेवरली हिल्स पोलो क्लब अपने चुनिंदा उत्पादों पर 50 प्रतिशत छूट दे रही है। आरऐंडबी अपनी अलग पेशकश चला रही है, जिसके तहत 2,500 रुपये का सामान खरीदने पर 1,250 रुपये का वाउचर मिल रहा है।

खुदरा कारोबारियों ने पहले ही जून महीने में सीजन की आखिरी बिक्री शुरू कर दी है और दो साल के बाद जोरदार बिक्री के कारण छूट पर उपलब्ध स्टॉक कम था और ग्राहकों ने पूरी कीमत वाले सामान खरीदने का विकल्प चुना। ब्रांडों ने बिक्री की अवधि भी घटाई है और छूट वाला स्टॉक कम रखा है। विजय सेल्स 70 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश कर रही है, लेकिन उसके ज्यादातर उत्पादों पर औसत छूट 10 से 20 प्रतिशत है। विजय सेल्स के एमडी नीलेश गुप्ता ने कहा, 'हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस की तुलना में बिक्री 20 से 22 प्रतिशत ज्यादा रहेगी।' उन्होंने यह भी कहा कि अगले 3 दिन के लिए आकर्षक बाईबैक और कैशबैक की पेशकश भी जा रही है।

रिलायंस डिजिटल भी डिजिटल इंडिया सेल के नाम से बिक्री की पेशकश कर रही है। कंपनी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सिटीबैंक आईसीआईसीआई, कोटक बैंक के डेबिट व क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तत्काल छूट मिलेगी, इसके अलावा अगली खरीद पर 10 प्रतिशत डिस्काउंट का वाउचर मिलेगा। क्रोमा भी स्वतंत्रता दिवस की बिक्री की पेशकश कर रही है।

डीएलएफ रिटेल की कार्यकारी निदेशक पुष्पा बेक्टर ने कहा, 'बिक्री अच्छी रही है और हम निश्चित रूप से बिक्री में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि रविवार को भीड़ बढ़ेगी। महामारी की तुलना में बिक्री पहले ही 20 प्रतिशत ज्यादा है और हम बेहतर सप्ताहांत की उम्मीद कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि सीजन की अंतिम बिक्री और स्वतंत्रता दिवस एक साथ है और खुदरा कारोबारी भारी छूट की पेशकश कर रहे हैं। वीमार्ट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ललित अग्रवाल ने कहा कि रक्षा बंधन और स्वतंत्रता दिवस की बिक्री एक साथ आने से बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है। रिटेल चेन एक खरीदें, एक मुफ्त पाएं जैसी पेशकश कर रही है और साथ ही महा बचत का डबल ऑफर भी चल रहा है।

रिटेलर्स को उम्मीद

- स्वतंत्रता दिवस पर कई ब्रांड अपने उत्पादों पर दे रहे हैं भारी छूट
- पेपे जींस अपने 35-40 फीसदी उत्पादों पर 50 फीसदी की छूट दे रही
- एल्डो चुनिंदा उत्पादों पर एक खरीदें व दूसरे पर 75 फीसदी की छूट दे रहा
- चुनिंदा उत्पादों पर बेवरली हिल्स पोलो क्लब 50 फीसदी की छूट ग्राहकों को दे रही है

अब अवैध उधारी ऐप की समस्या हो जाएगी खत्म

सुब्रत पांडा और पीरजादा अबरार
मुंबई, 12 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेश किए गए डिजिटल ऋण संबंधी दिशानिर्देश को फिनटेक और डिजिटल ऋण की दुनिया में सकारात्मक रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि इसके कड़े नियम की वजह से हाशिये के समाज को उधारी देने में लगी अवैध इकाइयों पर लगाम लग सकेगी। बहरहाल उद्योग के कारोबारियों का मानना है कि नए ढांचे का अनुपालन करने से अनुपालन लागत बढ़ सकती है और उनके कारोबारी मॉडल में परिचालन संबंधी जटिलता आ सकती है। उनका कहना है कि इसकी वजह से इस क्षेत्र में वृद्धि में कुछ समय के लिए सुस्ती आ सकती है।

उद्योग संघों फिनटेक एसोसिएशन फार कंज्यूमर इंपावरमेंट (फेस) और डिजिटल लेंडर एसोसिएशन आफ इंडिया (डीएलएआई) रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि व्याख्या संबंधी किसी विसंगति को दूर किया जा सके और उनके सदस्य नियामक द्वारा तय जरूरतें पूरी करने के लिए कदम उठा सकें।

नियामक ने डिजिटल ऋण ऐप (डीएलए) और ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) के लिए स्व नियामकीय संगठनों (एसआरओ) की स्थापना, को लेकर आगे और जांच की बात कही है, इन तमाम मसलों पर उद्योग संगठन नियामक से बातचीत जारी रखेंगे। मैकक्वैरी रिसर्च के सुरेश गणपति और परम सुब्रमण्यन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'इससे अनुपालन लागत और फिनटेक फर्मों के कारोबार के मॉडल की परिचालन संबंधी जटिलता बढ़ेगी। इसके सही सही असर को निर्धारित करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ दिशानिर्देशों को लागू करने की कवायद में फिनटेक फर्मों की वृद्धि में कुछ सुस्ती आ सकती है।' डीएलएआई के अध्यक्ष और जेस्टमनी के सीईओ व सहसंस्थापक लिजी चैपमैन ने कहा. 'दिशानिर्देशों ने यह साफ कर दिया है कि भारत ऐसा देश नहीं होगा, जहां नियामकीय खामियों का लाभ उठाकर कारोबार बढ़ाया जा सकता है।'

डीएलएआई के उपाध्यक्ष और फ्रेओ के सह संस्थापक अनुज कक्कड़ ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'उद्योग के हिसाब से यह सकारात्मक है क्योंकि नियामक ने यह निर्धारित किया है कि इसके हिस्सेदार किस तरह से काम करेंगे और सुनिश्चित किया है कि नवोन्मेष को दबाया न जाए।'

फेस की सीईओ सुगंध सक्सेना ने कहा, 'एसआरओ फ्रेमवर्क पर सावधानी से विचार किए जाने की जरूरत है। अब तक हमने एसआरओ का अनुभव सिर्फ एक सेग्मेंट एनबीएफसी-एमएफआई में लिया है। जब नियामक किसी इकाई या उत्पाद के बजाय किसी गतिविधि (डिजिटल उधारी) पर लागू होने वाले व्यापक दिशानिर्देशों के साथ आता है, तो कई विचार सामने आते हैं।' सुगंध ने कहा कि हम अभी नियमन का अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां स्पष्टीकरण की जरूरत है।

'रिकवरी एजेंट से कर्जदारों का उत्पीड़न नहीं कराएं'

भास्कर दत्त
मुंबई, 12 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों सहित नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों को सलाह दी है कि यह कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए कि वे और उनके रिकवरी एजेंट कर्ज वसूली की कवायद में किसी को डराने या उत्पीड़न करने का काम न करें।

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में कहा है कि ऐसा पाया गया है कि नियमन वाली इकाइयों द्वारा नियुक्त रिकवरी एजेंट वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग को नियंत्रित करने वाले निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

इन चिंताओं पर विचार करते हुए रिजर्व बैंक ने नियमन वाली इकाइयों से कहा है, 'वे या उनके एजेंट ऋण वसूली की कवायद में किसी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लें, जिससे कर्ज लेने व्यक्ति को मौखिक या भौतिक रूप से किसी तरह का उत्पीड़न हो या उनके या उनके परिवार के सदस्यों की निजता का उल्लंघन या सार्वजनिक रूप से उनका अपमान हो। इसमें उनके मित्रों से पूछताछ, मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, धमकी देना या गुमनामी कॉल करना शामिल है।' नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों से रिजर्व बैंक ने उधारी लेने वालों को सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल न करने को भी कहा है। इसमें यह भी गया है कि उधारी लेने वाले गलत या भ्रामक अभ्यावेदन के अधीन नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस सिलसिले में कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।

केंद्रीय बैंक का परिपत्र स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि भुगतान बैंक इसके दायरे से बाहर हैं। यह परिपत्र हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू है। एग्जिम बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नैशनल हाउसिंग बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नैशलन बैंक फॉर फाइनैंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड डेवलपमेंट सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान भी इसके दायरे में हैं। सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों को भी इस परिपत्र का पालन करना होगा। यह परिपत्र माइक्रोफाइनैंस ऋण पर नहीं लागू होगा।

बैंकों को सलाह

- ऋण वसूली की कवायद में उधार लेने वालों को रिकवरी एजेंट किसी भी तरह की धमकी नहीं दे सकते हैं
- सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कर्जदारों को फोन नहीं करें
- मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी और गलत संदेश कर्जदारों को नहीं भेजें

NLC India Limited
'Navratna' - Government of India Enterprise
No-135, EVR Periyar High Road, Kilpauk, Chennai-600 010, Tamil Nadu, India
CIN No.: L93090TN1956GOI003507, Website : www.nlcindia.in

CREATING WEALTH FOR WELLBEING

Extract of the Un-audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022
(₹ Crore unless otherwise stated)

Sl. No.	PARTICULARS	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2022 (Un-audited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Un-audited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2022 (Un-audited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Un-audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	3,094.46	2,579.26	2,359.96	9,856.48	3,862.91	3,085.89	3,036.46	11,947.94
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (before Exceptional & Rate Regulated Activity)	942.69	379.11	362.64	1,943.06	1,026.00	315.00	464.69	1,868.39
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional & Rate Regulated Activity)	757.15	495.11	424.35	2,606.42	854.08	406.61	563.36	2,603.14
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	506.08	439.73	267.22	1,236.78	568.83	331.16	357.59	1,115.65
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	513.79	457.84	266.97	1,263.54	577.07	350.31	357.32	1,143.88
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64
7	Other Equity excluding Revaluation Reserve	12,933.80	12,420.00	12,455.01	12,420.00	13,372.45	12,802.54	13,060.33	12,802.54
8	Securities Premium Account	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Net Worth	14,205.83	13,693.06	13,739.81	13,693.06	14,644.48	14,075.60	14,345.29	14,075.60
10	Paid up Debt Capital	9,963.82	10,239.03	14,212.31	10,239.03	22,292.10	22,058.37	26,307.09	22,058.37
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	0.70	0.75	1.03	0.75	1.52	1.57	1.83	1.57
13	Debt Service Coverage Ratio	2.91	2.00	1.05	1.47	2.20	1.72	1.10	1.35
14	Capital Redeemption Reserve	291.07	291.07	291.07	291.07	291.07	291.07	291.07	291.07
15	Debenture Redeemption Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Interest Service Coverage Ratio	7.42	6.97	4.62	5.78	6.83	5.77	4.70	5.19
17	Earnings per Equity Share (of Rs.10 each) from continuing operations (before adjustment of Net Regulatory Deferral Balances): Basic and diluted (in ₹)	4.56	2.48	1.56	7.29	4.96	1.89	1.99	6.05
18	Earnings per Equity Share (of Rs.10 each) from continuing operations (after adjustment of Net Regulatory Deferral Balances): Basic and diluted (in ₹)	3.65	3.17	1.93	8.92	4.10	2.39	2.58	8.05

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended Unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Unaudited financial results are available on the Stock Exchanges websites at **www.nseindia.com** & **www.bseindia.com** and on company's website i.e. **www.nlcindia.in**

Place: Neyveli
Date : 12.08.2022

Visit our website: **www.nlcindia.in**

For NLC India Limited
RAKESH KUMAR
Chairman cum Managing Director

PUBLIC SECTOR IS YOURS - HELP IT TO HELP YOU

सेज को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने की योजना

श्रेया नंदी
नई दिल्ली, 12 अगस्त

केंद्र सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए प्रस्तावित संवर्धित कानून 'डेवलपमेंट (इंटरप्राइज ऐंड सर्विस) हब बिल, 2022' के तहत आने वाले विनिर्माण व सेवा केंद्रों से जुड़ी गतिविधियों को आसान वित्तपोषण की सुविधा देने की योजना बना रही है। यह उन्हें बुनियादी ढांचे का दर्जा देकर दिया जाएगा, जैसा कि सड़क, रेल, जलमार्ग, हवाईअड्डों के लिए मिलता है। बुनियादी ढांचे का दर्जा मिलने से उनकी वित्त तक पहुंच सुधरेगी और कर्जदाताओं से आसान मानकों पर दीर्घावधि उधारी मिल सकेगी। सरकार चल रहे मॉनसून सत्र में देश विधेयक पारित होने की उम्मीद कर रही है। इस मामले से जुड़े लोगों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह विधेयक पारित होने के बाद वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से परामर्श कर वाणिज्य मंत्रालय नियमों को अंतिम रूप देने के लिए बारीकी से काम करेगा और इसे बुनियादी ढांचा उपक्षेत्र की मौजूदा मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

बीएस सूडोकू 4434 परिणाम संख्या 4433

		5					7	
1		4	7		9		5	
		8		1				3
	1							
		3		4	8			
			5				2	
5				2				1
4	9							
			4		7	6		

4	6	2	3	9	5	7	1	8
8	1	3	6	7	2	5	4	9
7	5	9	1	8	4	6	3	2
3	2	5	9	1	8	4	6	7
1	4	8	5	6	7	9	2	3
6	9	7	4	2	3	8	5	1
9	3	1	8	4	6	2	7	5
2	8	6	7	5	1	3	9	4
5	7	4	2	3	9	1	8	6

कैसे खेलें ? **बहुत आसान**

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

क्षेत्रीय मंडियों के भाव | दिल्ली | उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

दिल्ली
सराफा : दिल्ली में सोना 90 रुपया गिरकर 52,915 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में पीली धातु का भाव 53,005 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। इस दौरान चांदी की कीमत भी 374 रुपये के नुकसान के साथ 59,166 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी दिवस पर चांदी 59,540 रुपये प्रति किलो के भाव पर रही थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों ही लगभग स्थिर भाव पर रहे। सोना 1,789 डॉलर प्रति औंस पर रहा जबकि चांदी 20.37 डॉलर प्रति औंस पर मौजूद रही।

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2290/2300, गेहूं शरबती 3300/3500, चावल शरबती सेला 5300/5500, स्टीम 6000/6100, लालमती 6200/6300, चावल (सोना) 4600/4800, दाल अरहर सवा नं. 9600/10000, पटका 10600/11000, रिजैक्शन 7200/7400, चना दाल 5700/5800, चना देशी छना 5800/5900, चना चापा छना 6000/6100, एग्रो प्योर बेसन 2380, मटर देशी 5400/5600, उड़द साबुत (काला)8700/9800, दाल उड़द (काली) 8800/10000, उड़द धोया 9500/10600, मसूर छोटी 7300/7500, मलका 8400/8600, किरानाः जीरा 23400/25700, लालमिर्च गुंटूर 22500/31000, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 5000/5200, धनिया एमपी 12200/13600, छोटी इलायची (किलो) 780/1450, बड़ी इलायची 625/645, कालीमिर्च (किलो) 620/660, सुपारी (किलो) 470/520, सौंफ मोटी 15200/17500, मंगरैल 15500/16500, चिरौंजी (किलो) 1100/1200, मखाना 380/570

कानपुर
गेहूं लूज 2300/2325, जौ 3000/3050, चावल मसूरी 2600/2700, चावल मोटा 2325/2425, देशी चना 5200/5300, चना छना 5800/5900, दाल चना 5950/6050, देशी मटर 4800/4850, पिचकी 3400/3500, मटर दाल 4800/4900, अरहर लेमन 8000/8010, दाल अरहर 10700/11300, स्पेशल 10400/10600,उड़द एसक्यू 8800/8825, एफएक्यू 7750/7760, राजमा चित्रा 9300/13600, मूंग 6400/6600, मसूर छोटी 6950/7200, छांटी 8300/8600, सरसों 6300/6400, तिल सफेद 10000/10100, सोया (टीन) 2350/2375, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)2200/2300, सरसों खल 2600/2650, पामोलिन 2350/2400, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1850/1900, मधुसूदन देशी घी 8600, वासुदेव 8450, परम प्रीमियम 8600, पदम श्री 8500, लीलाधर 8500, अलसी 7200/7300, धनियाः लोकल 12800/13000, राजस्थान 13200/13400, बढ़िया 13700/13900, हल्दी 7800/10200, जीरा 23000/25100, अजवायन 12500/16500, मेथी 6000/6300, मखाना 350/500, कालीमिर्च (किलो) 600/640, लालमिर्च (किलो) तेजा 235/310, (334) न. 195/208, सुपारी (किलो) केरल 470/520, कर्नाटक चिकनी 500/520, गोला 20500/24000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1158, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1135, फ्लैक 1095, डीएमओ 915, टरपीन लैस बोल्ड 1150

जयपुर
दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मूंग मोगर 8200/8300, मोटा 8600/8800, उड़द मोगर 9500/9700, मोटा 10100/10500, चौला मोगर &, मोठ मोगर 7800/8000, मूंग दाल छिलका देशी 8100/8200, मलका 8400/8500, अरहर 9800/10600, मटर दाल 6000/6500, चना दाल मीडियम 5400/5500, बोल्ड 5600/5700, दलहनः उड़द साबुत देशी 7200/7300, मटर सफेद &, मोठ साबुत 6300/6400, काबली चना 7700/8500, चना (डिली.) 4975/5000, मूंग 6400/6500, राजमा शर्मिली 10000/10500, राजमां चित्रा 12500/13500, किरानाः हल्दी निजामाबाद 7600/8000, सांगली 8500/9300, हल्दी राजापुरी 13000/15800, लालमिर्च 24800/33000, कालीमिर्च (किलो) 550/650, धनिया 12800/14800, जीरा 24700/29000, अजवायन 14000/25000, सौंफ 16000/24000, मेथी 6000/6500, मेथी मशीन क्लीन 6900/7000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)200, राइसब्रान (अखाद्य) 195, खल सरसों 2700, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1800, लाल &, कंटीन्यूअस 1780, सरसों (टन) 21000, सूरजमुखी (टन) 24500, अनाजः गेहूं 2350/2400, आटा (50 किलो)1350, मैदा 1450, एनएनएस

डिस्क्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।